

Energy Compacts will be the most **inclusive** umbrella dedicated to bring together **voluntary commitments** on all SDG7 targets in support of achieving all SDGs by 2030 and net zero emissions by 2050.



एनर्जी कॉम्पैक्ट्स (EC) और राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDCs) के बीच अंतर:

- NDCs सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय जलवायु महत्त्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को संबोधित करते हैं जो पेरिस समझौते के तहत कानूनी रूप से आवश्यक हैं और ये संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश के उत्सर्जन प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- वही दूसरी ओर 'एनर्जी कॉम्पैक्ट्स' के तहत विशेषतः ऊर्जा प्रणाली और SDG7 पर केंद्रित विभिन्न प्रकार की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ, कार्य, पहल और भागीदारी शामिल हैं।
 - ये SDG7 लक्ष्यों को कवर करते हैं और इसमें वे लक्ष्य भी शामिल हैं, जो किसी देश के NDCs में परिलक्षित नहीं होते हैं।
- 'एनर्जी कॉम्पैक्ट्स' SDG7 से संबंधित सभी हितधारकों के लिये खुला हुआ है, जिसमें व्यवसाय, संगठन और उप-राष्ट्रीय प्राधिकरण शामिल हैं तथा वार्षिक तौर पर प्रतिबद्धताओं को लेकर प्रगत को ट्रैक करने हेतु तंत्र भी शामिल है।

एनर्जी कॉम्पैक्ट्स (EC) की आवश्यकता:

- विश्व स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जो औद्योगिकरण की समान प्रवृत्ति को जारी रखे हुए है।
- मौजूदा स्थिति
 - 789 मिलियन लोगों तक बजिली की पहुँच नहीं है (वर्ष 2018)।
 - 2.8 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा नहीं है (वर्ष 2018)।
 - कुल अंतिम ऊर्जा खपत का 17% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आता है (वर्ष 2017)।
 - 1.7% ऊर्जा दक्षता सुधार दर (वर्ष 2017)।

NTPC एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य:

- इसने वर्ष 2032 तक 60 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी करना है।
- एनटीपीसी ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान की सुविधा और ऊर्जा मूल्य शृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये कम-से-कम 2 अंतरराष्ट्रीय गठबंधन/समूह बनाएगी।

यूएन-एनर्जी

- यूएन-एनर्जी की स्थापना 'यूएन सस्टिम चीफ एक्जीक्यूटिव्स बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन' (CEB) द्वारा 2004 में ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर-एजेंसी सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के रूप में की गई थी।
- यह SDG7 और पेरिस जलवायु एजेंडा एवं व्यापक SDG एजेंडा के परस्पर संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों का समर्थन करता है।

डकिंड ऑफ एक्शन

- सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महत्त्वाकांक्षी, सार्वभौमिक और समावेशी 2030 एजेंडा के पर्यासों में तेज़ी लाकर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लिये वर्ष 2021-2030 को 'डकिंड ऑफ एक्शन' के रूप में घोषित किया था।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/energy-compacts>

